(b) No plant protection chemicals were distributed by the Coconut Development Board during the last three years. However, assistance for purchase of plant protection chemicals was provided @ Rs. 100/- per hectare during 1991-92 covering 4800 hectare area in Kerala.

(c) Information on the number of farmers benefited under the programme are not being maintained.

(d) No, Sir.

(e) The Coconut Development Board has proposed to implement a Comprehensive programme during Eight Plan period for improving the productivity of coconut and protection of coconut cultivation by removing diseased/unproductive palms, replanting with quality seedlings, adopting plant protection measures etc. During 1993-94, an outlay of Rs. 18.00 crores has been provided for the total coconut development programme, of which Rs. 4.796 crores will be utilised for the removal of diseased palms and plant proteciton.

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण

276 **श्री नृपेन्द्र सिंह मान : श्री सोमपाल** : क्या **खाद्य** मंत्री **ये** बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्रालय ने खाद्य मंत्रालय को सलाह दी है कि वह गेहूं के साथ-साथ मोटे अनाजों की भी पर्याप्त मात्रा में खरीद सुनिश्चित करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी गोदामों में कुल कितना अनाज खराब हुआ है ?

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में गोदामों में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

1098 RSS/94—4

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :

(क) और (ख) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग ने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों और राज्य की वसूली एजेंसियों के सहयोग से समर्थन मूल्य के अधीन खाद्यान्नों (मोटे अनाजों सहित) की वसूली करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपनी उपज न बेचनी पड़े।

रबी विपणन मौसम, 1990-91 से भारतीय खाद्य निगम को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मोटे अनाजों (दोनों रबी और खरीफ) के बारे में मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्रक एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की उपयुक्त एजेंसियों अर्थात् राजकीय सहकारी कृषि विपणन संघों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, आदि के साथ मिलकर ऐसे सभी मूल्य समर्थन परिचालन किए जा रहे हैं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1992-93 के दौरान 12 मई, 1993 तक 7.83 लाख मीटरी टन मोटे अनाजों की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम की इसी अवधि के दौरान मोटे अनाजों की नगण्य मात्रा की वसूली की गई थी। जहां तक वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान रबी के मोटे अनाजों (जौ) की वसूली करने का संबंध है भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य की वसूली एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों/बाजारों/मंडियों न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किए गए विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप मोटे अनाजों (जौ) की समस्त मात्रा खरीद ली जाए।

(ग) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान भंडारण (ढके हुए और कैप कम्पलैक्सों में) के दौरान तथा रेल/सड़क मार्ग में वर्षा, बाढ़ों और चक्रवातों के कारण तथा बहु हैंडलिंग की

वजह से खाद्यान्नों के स्टाक की निम्नलिखित मात्राएं क्षतिग्रस्त हो गई थीं :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

वर्ष	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की मात्रा
1989-90	0.25
1990-91	0.21
1991-92	0.19

वर्ष 1992-93 के आंकड़ों की अभी लेखा-परीक्षा की जानी है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम को 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान हुई कुल हानियों (भंडारण/मार्गस्थ) की स्थिति नीचे दी गई है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)
मूल्य करोड़ रुपयों में

वर्ष	कुल हानि	
	मात्रा	मूल्य
1989-90	2.96	87.89
1990-91	4.60	155.98
1991-92	5.90	219.70

वर्ष 1992-93 के आंकड़ों की अभी लेखापरीक्षा की जानी है।

(ङ) गोदामों में खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक ढंग से बनवाए गए मूषक और नमी प्रूफ गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण करता है।

(2) खाद्यान्नों का आवधिक निरीक्षण करने और उन्हें अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को लगाया जाता है।

(3) खाद्यान्नों को वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है और नियमित रूप से कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(4) कभी-कभार ढकी हुई भंडारण क्षमता की भारी कमी होने तथा संचलन संबंधी बाधाएं भी होने के कारण भारतीय खाद्य निगम को मजबूरन कैप (कवर और प्लिथ) नामक अस्थाई भंडारण के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई प्रणाली के अधीन खुले में गेहूं और धान का भंडारण करना पड़ता है। कैप में भंडारित खाद्यान्नों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं :—

(क) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उसे विशेष रूप से बनाई गई न्यून घनत्व की काली पोलीथीन की चादरों (एल.डी.पी.ई.) से ढका जाता है ताकि खाद्यान्नों की वर्षा से सुरक्षा की जा सके।

(ख) पोलीथीन की चादरों को उचित ढंग से बांधने के लिए नाइलोन की रस्सियां मुहैया की जाती हैं ताकि तूफानों के दौरान चादरों के उड़ने से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

(ग) मौसम की अनिश्चितता से चादरों और खाद्यान्नों की अतिरिक्त रक्षा करने के लिए प्रमुख कैप कांपलैक्सों में मोनोफिलामेंट के जाल और कवर टाप्स भी मुहैया किए जाते हैं।

(घ) स्टाक के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा आर्द्रता और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण जलवाष्प के संघनन, यदि कोई होता है, द्वारा क्षति को रोकने के लिए कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से वातन किया जाता है।

(ङ) गुम्बद के आकार के चट्टे लगाए जाते हैं ताकि ऊपरी सतह पर जल के किसी जमाव को रोका जा सके।

(च) कैप में भंडारित स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और कीट पीड़क जन्तुबाधा और चूहों, पक्षियों आदि जैसी अन्य कीट पीड़क जन्तुबाधा पर काबू पाने के लिए यथापेक्षित उपचार किए जाते हैं।

(छ) खाद्यान्नों का एक स्थान से दूसरे स्थान को यथासंभव ढकी हुई वैगनों में संचलन किया जाता है। जहां कहीं खुले वेगनों में स्टाक का संचलन किया जाता है, उन्हें तिरपालों से ढक दिया जाता है ताकि मार्ग में क्षति को रोका जा सके।

Setting up of a New University in Nagaland

*277. SHRI G. G. SWELL : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a new University in Nagaland;

(b) whether it will be under Central or State auspices; and

(c) if so, whether this would entail reorganisation of the North-Eastern Hill University ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) Government have enacted Legislation to set up a Central University in Nagaland.

Nagaland University Act has been assented to by the President.

Section 7 of the Act provides that (i) the jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Nagaland and (ii) that on and from the commencement of the Act, all Colleges, Institutions, Schools and Departments affiliated to, or admitted to the privileges of, or maintained by, the North-Eastern Hill University shall stand affiliated to, or admitted to the privileges of, or maintained by, the University of Nagaland and (iii) that on and from the date of commencement of the Act, the North-Eastern Hill University shall cease to exercise its jurisdiction in the State of Nagaland.

De-addiction Camps in India

@*278. SHRI N. E. BALARAM :

SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) how much amount has been collected as fee by different de-addiction centres in India State-wise, year-wise, during the last three years ;

(b) whether it is a fact that exorbitant fees charged by Government de-addiction centres prevent drug addicts from approaching such centres ;

(c) if so, what initiatives Government have taken to overcome this ;

(d) whether it is a fact that there is an acute shortage of Government run de-addiction centres in the country ; if so, state-wise details ; and

(e) the initiative taken by Government to overcome the situation ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) This Ministry provides grants to voluntary organisations for setting up and running of Deaddiction Centres for treatment and rehabilitation of drug addicts, 90 per cent of the total approved expenditure for the maintenance of these Centres is provided by the Ministry of Welfare, While the remaining 10 per cent is borne by the voluntary organisations.

(b) Welfare Ministry does not have any de-addiction centre of its own.

(c) Does not arise.

(d) and (e) 84 De-addiction Centres are being run by the NGOs with the help of this Ministry. The number of de-addiction Centres State-wise is given in the enclosed statement.

@ Previously starred Question 158, transferred from 5-5-1993.